



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1097 राँची, शुक्रवार,

7 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2018

संख्या-13/वरीय विविध-08/2018 का०-8382--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 4782 Of 2018 [Arising out of SLP(C) No.31167 of 2015] में दिनांक 11 मई, 2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित 22 न्यायिक पदाधिकारियों की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में की गयी सेवा (निम्नांकित तालिका के कॉलम II में अंकित तिथि से कॉलम III में अंकित तिथि तक की गयी सेवा) को उनके पेंशन एवं सेवानिवृत्तीय लाभ (retiral benefits) के लिए परिगणित किये जाने की सहमति दी जाती है :-

कॉलम संख्या	II	III
क्रम संख्या एवं नाम	अपर जिला न्यायाधीश, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि	अपर जिला न्यायाधीश, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के पद से हटाये जाने की प्रभावी तिथि
1. श्री ब्रजेश कुमार गौतम	02.02.2002	31.03.2011
2. श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	02.02.2002	31.03.2011

3. श्री कुमार कमल	02.02.2002	31.03.2011
4. श्री प्रदीप कुमार	02.02.2002	31.03.2011
5. श्री आशीष सक्सेना	12.08.2002	31.03.2011
6. श्री रघुबर दयाल	12.08.2002	31.03.2011
7. श्री अजीत कुमारनं०-1	12.08.2002	31.03.2011
8. श्री संदीप शर्मा	12.08.2002	31.03.2011
9. श्री आशुतोष दूबे	12.08.2002	31.03.2011
10. श्री राजेश कुमार पाण्डेय	12.08.2002	31.03.2011
11. श्री रामवचन सिंह	12.08.2002	31.03.2011
12. श्री प्रदीप कुमार चौबे	12.08.2002	31.03.2011
13. श्री सचिन्द्र कुमार पाण्डेय	12.08.2002	31.03.2011
14. श्री सुनील कुमार सिंह (नं०-1)	12.08.2002	31.03.2011
15. श्री राम बाबू गुप्ता	02.02.2002	31.03.2011
16. श्री रिजवान अहमद	02.02.2002	31.03.2011
17. श्री संजय कुमार चन्धरियावी	02.02.2002	31.03.2011
18. श्रीमती बबीता प्रसाद	02.02.2002	31.03.2011
19. श्री दीपक नाथ तिवारी	12.08.2002	31.03.2011
20. श्री महेश चन्दर वर्मा	12.08.2002	31.03.2011
21. श्री नलीन कुमार	12.08.2002	31.03.2011
22. श्री आलोक कुमार दूबे	02.02.2002	31.03.2011

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रभुनाथ शर्मा,

सरकार के अवर सचिव ।
